सं श्रो०वि०/एफ डी./138-86/34646.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ए०पी०एम० इलैक्ट्रो स्टैम्पिग (इण्डिया), प्रा. लि., 16/5 माईल स्टोन, मथुरा रोड. फरीदावाद के श्रीमक श्री वीरवहादुर पोडट मार्फत श्री श्रार. एन. पंकज, माधव सेवा समिति, जवाहर कालोनी, नांगला रोड़, फरीदावाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित. मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिसूचना सं० 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून 1978, के साथ पढ़ने हुए श्रिधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त श्रिधिन्यम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित! नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत श्रथवा सम्बन्धित मामला है :---

क्या भी वीरवहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं ग्रो॰ वि॰/एफ डी॰/101-86/34653.--चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. संजय इन्जिनियरिंग वर्कस, 2 एफ-1,एन. ग्राई. टी., फरीदाबाद के श्रमिक श्री रामपाल सिंह, पृत्र श्री हरि सिंह, डबुग्रा कलोनी, प्लाट नं 165-ए, फरीदाबाद तथा उसके अबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीदोगिक विवाद है;

क्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव, भौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधि सूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 परवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की घारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, परीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री रामपाल सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ी है? इस विन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है?

सं श्रो वि वि (एफ बी ) (85-86) 34660 — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० फर मा टो इण्डिया, प्लाट नं ० 270, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री किरपाल सिंह, एत श्री हुकम सिंह मार्पत बलबीर सिंह, गांव व डा ० गोच्छी, तहसील बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौदागिक विवादहै;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रव, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम. 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रीधसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए, ग्रिधसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवंरी, 1958 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के ग्रिधीन गठित श्रम न्यायलय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास भें देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं, या विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला हैं:—

क्या श्री किरपाल सिंह की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? दिनांक 22 सितम्बर, 1986

सं० श्रो० वि०/सोनीपत/ 45-86/35065.—चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० शादीराम उदमीराम पैट्रोल पम्प, गोहाना, जिला सोनीपत के श्रीमक श्री बहादुर चंद, पुत्र श्री लक्षा राम, मार्फत सीटू ग्राफिस सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीदोगिक विवाद है;

भीर चूं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत् निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, मृत, मौद्योगिक विवाद मिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई मिनितयों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मिधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी मिधिनियम की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादमस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचें लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादमस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत म्रथवा संबंधित है :—

क्या श्री बहादुर चन्द की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?